बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 136 ● नई दिल्ली ● वीरवार 12 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मेन कोर्स नहीं बनेगा, एलपीजी संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट की लॉयर्स कैंटीन पर चस्पा किया नोटिस

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चलते संघर्ष के कारण एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के चलते दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन ने मेन कोर्स बनाना बंद करने की घोषणा की है। बताते चलें कि हाई कोर्ट स्थित वकीलों को भोजन उपलब्ध कराने वाली कैंटीन ने आज यानी 11 मार्च को वकीलों की जानकारी के लिए कैंटीन में ही एक नोटिस लगाया है। इस नोटिस में लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट वकील कैंटीन मुख्य भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएगी। लॉयर्स कैंटीन के संदीप शर्मा की तरफ से जारी इस नोटिस में लिखा है, इस वक्त एलपीजी गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता के चलते हमें खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लॉयर्स कैंटीन (वकीलों की कैंटीन) में मेन कोर्स नहीं बना पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की इजाजत दी-13 साल से कोमा में है बेटा, माता-पिता ने लगाई थी गुहार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छामृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मंजूरी दे दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। देश में इस तरह का यह पहला मामला है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है, उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छामृत्यु देने की अपील पर सुनाया। हरीश अपनी मां निर्मला राणा के साथ। परिवार ने बताया कि बेटे के इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन अब आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बेटे की तकलीफ भी नहीं देखी जाती। हरीश अपनी मां निर्मला राणा के साथ। परिवार ने बताया कि बेटे के इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन अब आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बेटे की तकलीफ भी नहीं देखी जाती। फैसले पर पिता अशोक ने कहा- हम इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। कौन से माता-पिता अपने बेटे के लिए ऐसा चाहेंगे। पिछले 3 साल से हम यह मामला लड़ रहे थे। अब उसे एम्स ले जाया जाएगा। वह पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर हुआ करता था।

हरीश हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरे थे, तब से बिस्तर पर

दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह न कुछ बोल सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने-पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेडसोर्स यानी गहरे घाव बन गए हैं। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक है। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में शेक्सपीयर का जिक्र किया

जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक हेलमेट की पंक्ति "To be or not to be" का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है।

लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय दो आधारों पर होना चाहिए

यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो।

यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो।

अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना न हो, तो यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर कानून बनाने पर विचार करने का भी कहा। फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर दो मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है।

लोकसभा अध्यक्ष पर रार - नेहरू-1954 के उदाहरण पर भिड़े राहुल और रविशंकर, रिजिजू के बयान पर सदन में फिर हंगामा

नई दिल्ली। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई। भाजपा सांसद मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि स्पीकर को हटाने के इस प्रस्ताव को किसी नेता के अहंकार (ईगो) को संतुष्ट करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने दुख जताया कि सदन को आज ऐसे विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है जो सिर्फ एक नेता की जिद का नतीजा है। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस चर्चा के दौरान चेयरपर्सन का पैनल सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता। उन्होंने संसदीय नियमों और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए। प्रसाद के इन आरोपों पर सदन में काफी हंगामा हुआ। इसके बाद कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे दिलीप सैकिया ने राहुल गांधी को जवाब देने का मौका दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में कई बार बोलने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। जवाब में रविशंकर प्रसाद ने फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर भारतीय संसद, संविधान और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले इन्हीं संस्थाओं के तहत कई चुनाव जीते हैं, लेकिन अब वह इन्हीं पर निशाना साध रही है।

रिजिजू और जयराम रमेश में हुई तीखी बहस

चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच 1954 के एक पुराने मामले को लेकर तीखी बहस हुई। किरेन रिजिजू ने सदन में गर्व से कहा कि मौजूदा सरकार ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया है। उन्होंने इसकी तुलना साल 1954 से की, जब देश के पहले स्पीकर जी.वी. मावलंकर के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव आया था। रिजिजू ने दावा किया कि उस समय इस पर सिर्फ ढाई घंटे की बहस हुई थी। रिजिजू के अनुसार, उस समय विपक्षी दल ने चर्चा के लिए पूरे एक दिन की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केवल डेढ़ घंटे का समय दिया था। काफी बहस के बाद उस समय दो घंटे की चर्चा पर सहमति बनी थी। रिजिजू ने कहा कि आज की सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है और विपक्ष को दो दिन का समय दे रही है। उन्होंने टीएमसी सांसद सौगत राय पर भी निशाना साधा, जिन्होंने चर्चा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के फैसले पर सवाल उठाए थे।

जयराम रमेश ने दावों किया पलटवार

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रिजिजू के इन दावों पर तुरंत पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 1954 की बहस के कुछ दस्तावेज साझा किए। रमेश ने बताया कि 18 दिसंबर 1954 को प्रधानमंत्री नेहरू खुद पूरी बहस के दौरान सदन में बैठे थे और उन्होंने चर्चा में हिस्सा भी लिया था। नेहरू ने खुद डिप्टी स्पीकर से अनुरोध किया था कि चर्चा का ज्यादातर समय विपक्ष को मिलना चाहिए। नेहरू का कहना था कि सरकारी पक्ष को ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए ताकि विपक्षी सदस्य अपनी बात विस्तार से रख सकें। जयराम रमेश ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 1954, 1966 और 1987 में जब भी स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, तब सदन में डिप्टी स्पीकर मौजूद थे। लेकिन 2019 के बीच से लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। रमेश ने इसे संविधान का स्पष्ट उल्लंघन बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1954 में कांग्रेस के पास 489 में से 364 सांसद थे, फिर भी नेहरू ने विपक्ष की आवाज को महत्व दिया था।

विपक्ष ने स्पीकर पर लगाए पक्षपात आरोप

विपक्ष ने मौजूदा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को जरूरी विषयों पर अपनी बात रखने से रोका गया। विपक्ष ने महिला सांसदों के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों को भी गलत बताया। विपक्षी सदस्यों ने सांसदों के निलंबन पर सवाल उठाए और कहा कि सदन को बिना किसी सरकारी दबाव के निष्पक्ष तरीके से चलाना चाहिए।

सत्ता पक्ष ने ओम बिरला की किया बचाव

दूसरी तरफ, सत्ता पक्ष (एनडीए) ने ओम बिरला का बचाव किया। सरकार ने कहा कि विपक्ष यह प्रस्ताव सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए लाया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि स्पीकर पूरी तरह निष्पक्ष हैं और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई उनके खराब व्यवहार की वजह से हुई थी। संविधान के अनुसार, स्पीकर चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन ओम बिरला ने मंगलवार की कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया। इस चर्चा का अंत बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ होने की उम्मीद है।

कौन हैं तरनजीत सिंह संधू? जिन्होंने ली दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ

नई दिल्ली । पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। यह समारोह लोक निवास में आयोजित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संधू ने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका मामलों के सबसे अनुभवी भारतीय राजनयिकों में से एक रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन, डी.सी. स्थित भारतीय दूतावास में कई बार कार्य किया है। संधू फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। 63 वर्षीय संधू जुलाई 2005 से फरवरी 2009 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में भी रहे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैं उपराज्यपाल का स्वागत करती हूं। आप दिल्ली को और अधिक गति से बढ़ाने के लिए यहां आए हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि आपके यहां होने से दिल्ली की गति और बढ़ेगी। दिल्ली की समस्याओं का और समाधान मिल पाएगा। आपके मार्गदर्शन में दिशा निर्देश के अनुसार दिल्ली सरकार काम करेगी तरनजीत सिंह संधू का राजनयिक करियर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाशिंगटन, डी.सी. में भारतीय दूतावास में उनका अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में भी उन्होंने सेवा दी थी। यह उनके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गहरी समझ को दर्शाता है। संधू ने 2024 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने पंजाब के अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि, उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह उनकी प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवा की नई पारी है। बता दें कि तरनजीत सिंह संधू विनय कुमार सक्सेना की जगह ले रहे हैं, जिन्हें हाल ही में लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। संधू 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे हैं और अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं।

एलपीजी गैस संकट बढ़ने पर केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, बोले- ऐसा लग रहा जैसे ट्रंप के दबाव में काम कर रहे

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में बढ़ते झगड़े की वजह से इम्पोर्टेड गैस सप्लाई में रुकावटों के बीच आपूर्ति की समस्या अब देश में भी महसूस होने लगी है। ऐसे में दिल्ली के कई हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर की किल्लत सामने आ रही है, जिससे गैस एजेंसियों के साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। सप्लाई में देरी और सीमित उपलब्धता के कारण कई जगहों पर सिलिंडर की डिलीवरी प्रभावित हो रही है। इसने आम लोगों की समस्या और परेशानियां दोनों बढ़ा दी है। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने गैस की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा ने केजरीवाल पर संकटकाल में अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है। देश में एलपीजी का उत्पादन लगभग 50फीसदी तक घट चुका है। एलपीजी पर निर्भर कई उद्योगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। इस फैसले के कारण देश के बड़े शहरों में कई रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस समय देशभर में शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है, और अगर यही हालात रहे तो लोगों को अपनी शादियां तक टालनी पड़ सकती हैं। केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने भारत को एक गंभीर संकट में डाल दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो भारत जैसे महान देश को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया गया हो। आज स्थिति यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर बताया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। यहां तक कि अमेरिका के छोटे-छोटे अधिकारी भी भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की परंपरागत निरपेक्ष राजनीति से दूर हटने का आरोप लगाया। आप के साथ विपक्ष के दूसरे दलों ने भी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष चालू संसद सत्र में भी इस विषय पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के हमलों का जवाब देते हुए उन्हें मौकापरस्त राजनीति करने वाला नेता करार दिया।

सचदेवा ने कहा कि ईरान-अमेरिका युद्ध एक वैश्विक संकट का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में गैस और पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस उपलब्धता को लेकर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि संकट को देखते हुए गैस के उपयोग को प्रमुखता के आधार पर बांटा जा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में सबको साथ खड़े होकर इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी केजरीवाल को राजनीति का अवसर दिखाई दे रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सचदेवा ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर देश के संकट के समय में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पहले कोविड काल में भी इन नेताओं ने राजनीति करने की कोशिश की थी और इस समय भी वे यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

ममता बनर्जी ने तो राष्ट्रपति मुर्मू तक को नहीं बख्शा !

यह बात जगजाहिर है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी अपने ज़िद्दीपन और अक्खड़पने के लिए मशहूर हैं। इससे पूर्व भी एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कार्यक्रम आयोजित किया था तो वे उनके बुलाने के बावजूद नहीं पधारीं। वह किसी को भी कुछ भी बोल देती हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जेपी नड्डा पर फब्तियां कसी थीं। वह किसी को भी कुछ भी उल्ल-जलूल बोल देती हैं और फिर उन अपशब्दों को वापिस भी नहीं लेतीं। वह समझती हैं कि उन पर सात खून माफ़ हैं! भाजपा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कई बार उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, खासकर चुनावों के समय। भाजपा ने आरोप लगाया कि कई कार्यकर्ताओं की हत्या और मारपीट की घटनाएं हुईं। असेंबली और लोकसभा इलेक्शन के दौरान और उसके बाद भाजपा ने दावा किया कि उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया और कई लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। भाजपा नेताओं का आरोप रहा कि राज्य की पुलिस और प्रशासन का उपयोग विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए किया गया। हुआ यह कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पश्चिम-बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचीं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी उपमंडल के विधाननगर पहुंचीं, जहां उन्होंने पश्चिम-बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति अपनी नाराजगी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें मेरे कार्यक्रम में साथ होना चाहिए था। राष्ट्रपति ने कहा, मैं बंगाल की बेटी हूं, फिर भी मुझे यहां आने की अनुमति नहीं है। ममता मेरी छोटी बहन जैसी हैं, पता नहीं, शायद वह मुझसे नाराज हैं, इसीलिए मुझे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहां (गोसाईंपुर) जाना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है। राष्ट्रपति को मूल रूप से सिलीगुड़ी के बिधाननगर उपमंडल में कार्यक्रम को संबोधित करना था लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसलिए कार्यक्रम स्थल को बागडोगरा के गोसाईंपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद वह मूल स्थल पर गई और वहां अपनी बात रखी। दरअसल राष्ट्रपति को मूल रूप से सिलीगुड़ी के बिधाननगर उपमंडल में कार्यक्रम को संबोधित करना था लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसलिए कार्यक्रम स्थल को बागडोगरा के गोसाईंपुर में स्थानांतरित कर दिया था। अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद वह मूल स्थल पर गई और वहां अपनी बात रखी। राष्ट्रपति मुर्मू की नाराजगी के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर राज्य सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, आज पश्चिम-बंगाल में घटी घटनाओं से ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में संवैधानिक ढांचे के पूर्ण पतन का संकेत मिलता है। एक दुर्लभ और अभूतपूर्व घटनाक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी यात्रा के दौरान तैयारियों और प्रोटोकॉल के अभाव पर खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन के लिए अनुमति देने से इन्कार कर दिया, जहां स्वयं राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थीं। जब कोई राज्य सरकार भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा का अनादर करने लगती है तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है, बल्कि संवैधानिक मर्यादा और शासन व्यवस्था के पतन को भी दर्शाता है। यह केवल अभद्रता नहीं है। यह संस्थागत अनादर है और एक बार फिर इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में शासन व्यवस्था किस प्रकार अराजकता में डूब गई है। उन्होंने कहा कि साल 2003 को संथाल समुदाय के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस साल, संथाल भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संथाल भाषा में ओल चिकी स्क्रिप्ट में लिखा गया भारत का संविधान जारी किया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी स्क्रिप्ट बनाई थी। हाल ही में हमने इस इन्वेंशन की 100वीं सालगिरह मनाई है। उनके योगदान ने संथाल भाषा बोलने वालों को अपनी बात कहने का एक नया मौका दिया। उन्होंने बिदु चंदन, खेरवाल बीर, दलेगे धन, और सिदो कान्हू हूल संताल हुल जैसे नाटक भी लिखे। इस तरह उन्होंने संथाल समुदाय में साहित्य और सामाजिक चेतना की रोशनी फैलाई। संथाल समुदाय के लोगों को दूसरी भाषाएं और स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा, आज समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है। आदिवासी युवाओं को शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के जरिए आगे बढ़ना चाहिए लेकिन इन सभी कोशिशों में उन्हें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। इससे हमें एक सशक्त समाज और एक मजबूत भारत बनाने में मदद मिलेगी। यह देश कानून से चलता है न कि हठधर्मिता से। अतः ममता दीदी को सभी का मान-सम्मान करना चाहिए।

खाड़ी युद्ध व घरेलू राजनीति

पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल व अमेरिका युद्ध के चलते पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो संकट गहराता जा रहा है उससे अब भारत भी अछूता नहीं रहा है और देश ने ईंधन गैस के मोर्चे पर सतर्कता दिखानी शुरू कर दी है। इस सन्दर्भ में केन्द्र की मोदी सरकार ने आवश्यक उपभोक्ता सामग्री अधिनियम लागू कर दिया है जिसके चलते किसी भी जरूरी सामान की जमाखोरी या जखीरेबाजी नहीं की जा सकती। ऐसा करना इस कानून के तहत दंडनीय अपराध होता है। सरकार ने दो दिन पहले ही गैस ईंधन की किल्लत को देखते हुए इसकी कीमत में थोड़ा इजाफा भी किया था। इससे समझा जा सकता है कि दुनिया के किसी भी कोने में छिड़े युद्ध के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसकी मूल वजह यह है कि विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक- दूसरे से जुड़ने के बाद परस्पर निर्भरता के दौर में पहुंच चुकी हैं। यह परिवर्तन 1990 में विश्व व्यापार संगठन के मूर्त रूप में होने के बाद आया है। दुनिया के अधिसंख्य देश इस संगठन के सदस्य बन चुके हैं परन्तु अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के पुनः राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी नीतियों से यह संगठन लगातार अप्रासंगिक होता नजर आ रहा है क्योंकि ट्रम्प ने द्विपक्षीय आधार पर विभिन्न देशों के साथ आपसी कारोबारी समझौते की झड़ी लगा रखी है जिसकी वजह से हर देश को अपने कारोबारी राष्ट्रीय हितों को साधने की फिक्र हो गई है। मगर ट्रम्प ने अमेरिका को पुनः महान बनाने का जो राजनीतिक नारा दे रखा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में स्थापित वह व्यवस्था लड़खड़ा रही है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ हुआ था। इसके अनुसार दुनिया का हर छोटा- बड़ा देश एक-दूसरे की भौगोलिक संप्रभुता का सम्मान करेगा और अपनी ताकत के बूते पर किसी भी कमजोर देश की राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं करेगा लेकिन हमने देखा है कि 1945 के बाद से भी दुनिया के विभिन्न देशों में युद्ध हुए हैं और संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित मानकों का हनन हुआ है। हैरत करने वाली बात यह है कि कमोबेश रूप से इन सभी युद्धों में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है परन्तु 1990 से पहले सोवियत संघ के विघटन से पूर्व विश्व में दो महाशक्तियों सोवियत संघ व अमेरिका के बीच शक्ति सन्तुलन इस प्रकार रहता था कि दोनों ही दुनिया में अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों को अपने खेमों में लाने के प्रयास करते रहते थे। 1990 के बाद पूरा विश्व एक पक्षीय या एकल ध्रुवीय होता चला गया। अतः आज पूरे विश्व में जो शक्ति सन्तुलन है वह स्वाभाविक रूप से अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है।

ऐसे माहौल में ईरान के साथ पश्चिम एशिया में जो इजराइल व अमेरिका मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं उससे पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता संकट में पड़ती नजर आ रही है जिसकी चपेट में अधिसंख्य खाड़ी व अरब देश आ चुके हैं क्योंकि लगभग इन सभी देशों में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बहुत प्रभावी मानी जाती है। इसका कारण इन देशों की अपनी घरेलू राजनीतिक व शासकीय मजबूरियां मानी जाती है। इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पैट्रोलियम तेल के उत्पादन पर टिकी हुई है अतः ईरान-इजराइल युद्ध की चपेट में इन देशों के आ जाने के बाद सबसे बुरा असर पैट्रोलियम तेल की सप्लाई पर ही होना था। भारत चूंकि अपनी तेल व गैस ऊर्जा की आवश्यकताओं की खपत 85 प्रतिशत आयात से ही करता है अतः इस मोर्चे पर इसे सतर्कता बरतनी ही थी। इस वातावरण में हमें देश की राजनीति की परख करनी होगी समझना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र भारत को संसद से लेकर सड़क तक किस प्रकार के विमर्श के भीतर अपने राष्ट्रीय हितों को साधना चाहिए। फिलहाल संसद का सत्र चल रहा है और देश की विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशियाई युद्ध को लेकर व्यापक बहस व चर्चा कराई जाये। लोकतन्त्र में ऐसी मांग को खारिज भी नहीं किया जा सकता है परन्तु असली सवाल यह है कि ऐसे माहौल में देश के सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य क्या बनता है। यह कर्तव्य सर्वप्रथम राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने का होता है। हम मानते हैं कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं वे सभी राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित हैं, बेशक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं परन्तु सभी भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहते हुए सामाजिक व राष्ट्रीय उत्थान के पक्षधर होते हैं। अतः संसद के भीतर इन सभी दलों में इस बात पर मतैक्य कायम क्यों नहीं हो सकता कि ईरान-इजराइल युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भारत का एकाग्र नजरिया क्या हो जिससे भारतीय हित पूरी तरह संरक्षित रह सकें। हम देख रहे हैं कि इस युद्ध के चलते अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भावों में किस तरह का भूचाल आया हुआ है। विगत दिन ही कच्चे तेल के भाव 116 डॉलर प्रति बैरल तक जाने के बाद आज 88 डॉलर प्रति बैरल पर टिके परन्तु इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि भाव इसी स्तर पर स्थिर हो जायेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ईरान-इजराइल युद्ध बहुत लम्बा न खिंचे और इसका अन्त जल्दी से जल्दी हो। इस सन्दर्भ में विदेश मन्त्री श्री एस. जयशंकर का कल संसद में दिया गया यह बयान महत्वपूर्ण है कि भारत हर मसले का हल शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता के माध्यम से चाहता है। यह स्वतन्त्रता के बाद से भारत की घोषित नीति है और वह मानता है कि किसी भी देश में किस प्रकार की सरकार हो इसका अधिकार केवल उस देश के लोगों का ही होता है। अतः पश्चिम एशिया के युद्ध में किसी एक पक्ष के खेमे में भारत के खड़े होने का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन हालात के व्यावहारिक पक्ष का भी भारत को ख्याल रखना होगा और इस प्रकार अपनी रणनीति तय करनी होगी जिससे उसके राष्ट्रीय हितों पर किसी भी प्रकार से चोट न आये।

सम्पादकीय...

यूरोप का हुआ बुरा हाल, रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देश अब मास्को से मांग रहे गैस और तेल

जो यूरोप कल तक रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा था और उससे गैस तथा तेल खरीदने वाले देशों पर पेनल्टी लगाने की मांग करते हुए यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा था, वहीं यूरोप अब मध्य पूर्व में संकट गहराते ही फिर से रूस की ओर देखने लगा है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष तथा फारस की खाड़ी में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में ऊर्जा संकट से जूझता यूरोप रूस से गैस और तेल की संभावित आपूर्ति को लेकर नई चर्चा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों में रूस को अप्रत्याशित लाभ की स्थिति में ला खड़ा किया है। हम आपको बता दें कि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। फारस की खाड़ी के प्रमुख समुद्री मार्ग हार्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। ईरान से जुड़े तनाव और संभावित आपूर्ति बाधा की आशंका के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत प्रति बैरल सौ डॉलर से ऊपर पहुंच गई। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद कीमतों में कुछ गिरावट आई, फिर भी युद्ध से पहले की तुलना में तेल करीब सत्ताइस प्रतिशत महंगा बना हुआ है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ रूस को मिल सकता है। रूस पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने उस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के कारण इन प्रतिबंधों का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है। ऊंची कीमतों के कारण रूस को अपने तेल निर्यात से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। अमेरिका ने भारत को भी सीमित रूप से अस्थायी छूट देते हुए रूसी कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दी है। इस निर्णय के बाद रूस के तेल निर्यात में तेजी आई है। पहले जहां रूसी तेल लगभग पचास डॉलर प्रति बैरल के आसपास बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत करीब नब्बे डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे रूस को राजस्व में भारी बढ़ोतरी मिल रही है। ऊर्जा बाजार के आंकड़े बताते हैं कि समुद्र में टैंकरों पर जमा रूसी तेल का भंडार भी तेजी से कम हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि खरीदार देशों तक आपूर्ति तेजी से पहुंच रही है। फरवरी के अंत तक जहां टैंकरों में लगभग एक सौ बत्तीस मिलियन बैरल रूसी तेल जमा था, वहीं अब यह घटकर करीब एक सौ अठारह मिलियन बैरल रह गया है। इसका अर्थ है कि वैश्विक बाजार में रूसी तेल की मांग फिर बढ़ने लगी है। यदि मध्य पूर्व में संघर्ष लंबा चलता है और खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात बाधित होता है तो रूस को अरबों डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऊंची कीमतों और आपूर्ति संकट के चलते रूस को आय में कई अरब डॉलर का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संकेत दिया है कि यदि यूरोपीय देश राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर दीर्घकालिक सहयोग चाहते हैं तो रूस उन्हें फिर से तेल और गैस आपूर्ति करने को तैयार है। पुतिन का कहना है कि रूस ने कभी यूरोप के साथ ऊर्जा सहयोग से इंकार नहीं किया, लेकिन

खिलाफत से खामेनेई तक - भारत में मुस्लिम लामबंदी की राजनीति

ईरान के एक प्रमुख मजहबी नेता की हत्या, जिसे आम तौर पर लोगों की स्मृति में रुहोल्लाह खोमैनी जैसे व्यक्तित्वों से जोड़कर देखा जाता है, कई बार ईरान की सीमाओं से बाहर भी विरोध-प्रदर्शनों की वजह बनती रही है। भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती रही हैं। हाल में अमेरिका-इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में खामेनेई की हत्या के बाद भारत के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हुए। ये घटनाएं केवल विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सवाल नहीं है।

वे भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक सोच, पहचान, मजहबी भावनाओं और भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के बीच मौजूद जटिल रिश्तों को भी सामने लाती हैं। वैश्विक इस्लामी व्यक्तित्वों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं से परे चला जाता है। लेकिन इस प्रवृत्ति को भारत के संवैधानिक ढांचे, ऐतिहासिक अनुभवों और पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति के संदर्भ में समझना जरूरी है। इतिहास की परछाइयां- भारतीय मुसलमानों में मजहबी प्रेरणा से होने वाली राजनीतिक लामबंदी की जड़ें खिलाफत आंदोलन (1919-1924) तक जाती हैं। यह आंदोलन भारतीय राजनीति में पैन-इस्लामिक भावनाओं के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। अली बंधुओं जैसे नेताओं ने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और उस दौर में हिंदू-मुस्लिम एकता की भावना को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी भी कुछ समय तक इस आंदोलन के साथ खड़े रहे। हालांकि आलोचकों का मानना है कि खिलाफत आंदोलन ने मजहबी निष्ठा और राष्ट्रीय हित के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। उनके अनुसार इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में आस्था-आधारित लामबंदी की एक ऐसी मिसाल स्थापित की, जिसका असर आगे चलकर भी दिखाई दिया। इसी दृष्टिकोण से आज ईरान या पश्चिम एशिया की घटनाओं पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को कभी-कभी पैन-इस्लामिक एकजुटता के विस्तार के रूप में देखा जाता है, जहां मजहबी जुड़ाव क्षेत्रीय राष्ट्रवाद से ऊपर दिखाई देता है लेकिन ऐतिहासिक तुलना करते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि खिलाफत आंदोलन औपनिवेशिक शासन के दौर में हुआ था, जबकि आज का भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। फिर भी कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मजहबी पहचान को राष्ट्रवाद से ऊपर रखने की प्रवृत्ति और राजनीतिक तुष्टिकरण की राजनीति के बीज उसी दौर में पड़े, जिनका इस्तेमाल बाद के समय में मुस्लिम समाज को संगठित करने के लिए किया गया। भारत का संविधान एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करता है जो किसी मजहब को विशेष महत्व नहीं देता और न ही किसी मजहब के प्रति भेदभाव करता है। जब मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्ग विदेश में किसी शिया मजहबी नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हैं तो आलोचक इसे राष्ट्र से ऊपर मजहब की प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार यह सवाल उठता है कि किसी विदेशी मजहबी नेता के लिए भारत में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन क्यों होते हैं लेकिन दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहचान की अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है।

विवाद तब और तीखा हो जाता है जब विरोध प्रदर्शनों को चयनात्मक माना जाता है। कुछ आलोचक पूछते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार या कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों पर इसी तरह की व्यापक लामबंदी क्यों नहीं दिखाई देती। ऐसी तुलना इस तर्क को मजबूत करती है कि कुछ विरोध-प्रदर्शनों के पीछे सार्वभौमिक मानवीय चिंता के बजाय मजहबी प्रतीकवाद अधिक प्रभावी होता है। हालांकि सामाजिक आंदोलनों का चरित्र हमेशा एक जैसा नहीं होता। सामूहिक लामबंदी नेतृत्व, स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, मजहबी संबद्धताओं और मीडिया की भूमिका जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। इसलिए इसे केवल राष्ट्र बनाम मजहब के सरल द्वंद्व में बांध देना भी बौद्धिक रूप से अधूरा होगा। पैन-इस्लामवाद एक राजनीतिक और मजहबी विचारधारा है जिसका उद्देश्य 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों (ब्रिटेन, फ्रांस और रूस)के खिलाफ वैश्विक मुस्लिम समुदाय को एक मंच पर लाना था। जमाल अल-दीन अल-अफगानी जैसे विचारकों ने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार इस्लाम केवल एक मजहब नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जो जातीय और राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर मुसलमानों की एकता पर जोर देती है। रुहोल्लाह खोमैनी जैसे नेताओं ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें ईरानी क्रांति को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया गया। विशेष रूप से शिया समुदायों के लिए खोमैनी मजहबी नेतृत्व और पश्चिमी प्रभाव(खासकर अमेरिका)के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए लेकिन इस्लामी दुनिया खुद ही गहरे सांप्रदायिक और भू-राजनीतिक विभाजनों से घिरी हुई है। शिया-सुन्नी मतभेद, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाएं और अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय हित किसी भी एकीकृत मुस्लिम एकता की अवधारणा को जटिल बना देते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव, कई सुन्नी बहुल देशों के साथ ईरान के विवाद और ईरान-इराक युद्ध जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि मुस्लिम बहुल देश भी एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं।

दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कई मौकों पर ईरान ऐसे मुस्लिम देशों के खिलाफ संघर्ष की स्थिति में रहा है जो पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी रखते हैं। कुछ विश्लेषक ऐसे प्रदर्शनों को सभ्यताओं के टकराव की अवधारणा के संदर्भ में भी देखते हैं। एक ओर भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भी उसके ऐतिहासिक और ऊर्जा-आधारित संबंध रहे हैं। इसलिए नागरिक समाज के विरोध-प्रदर्शन को सीधे-सीधे भारत की आधिकारिक विदेश नीति से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में विरोध और असहमति भी राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक हिस्सा होते हैं। यह आलोचना कि कुछ बुद्धिजीवी मजहबी आधार पर होने वाले प्रदर्शनों पर चुप रहते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर चल रही व्यापक बहस का हिस्सा है। ईरान के एक मजहबी नेता की हत्या के विरोध में भारत में हुए प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मजहबी पहचान और संवैधानिक राष्ट्रवाद के बीच मौजूद तनाव को उजागर करते हैं। खिलाफत आंदोलन जैसे ऐतिहासिक उदाहरण हमें संदर्भ जरूर देते हैं लेकिन वे वर्तमान परिस्थितियों को पूरी तरह निर्धारित नहीं करते। जहां आलोचक इन प्रदर्शनों को राष्ट्र से ऊपर मजहब रखने की प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं, वहीं समर्थकों का तर्क है कि लोकतंत्र में सीमाओं के पार भावनात्मक एकजुटता व्यक्त करना भी नागरिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। पैन-इस्लामिक भावनाएं, सांप्रदायिक विभाजन, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं और भारतीय मुसलमानों की बहुस्तरीय पहचान, ये सभी एक साथ मौजूद हैं। इसलिए पूरे घटनाक्रम को केवल तुष्टिकरण या सभ्यताओं के संघर्ष के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। एक गंभीर और संतुलित विश्लेषण को भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भीतर मजहब, राजनीति और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के बीच मौजूद संबंधों को समझना होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण से यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भावनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय हित भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत-ईरान संबंधों के संदर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने कई मौकों पर भारत के रुख से असहमति जताई है। इसलिए विदेश नीति के स्तर पर भारत को अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर ही संतुलित रुख अपनाना होगा।

अमेरिका का डर्टी गेम- साम्राज्यवाद फिर से अपने पंजे दिखा रहा है

राम पुनियानी

दूसरी ओर ईरान बातचीत की मेज़ पर आने को तैयार था और वार्ता से निकलने वाले कुछ बिंदुओं पर समझौता करने के लिए भी तैयार था। लेकिन बातचीत के बीच ही इज़रायल-अमेरिका धुरी ने युद्ध शुरू करने का फ़ैसला कर लिया और युद्ध के शुरुआती चरण में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलों में दो घटनाएं विशेष रूप से सामने आईं। पहली, खामेनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या। दूसरी, एक स्कूल पर बमबारी, जिसमें 165 किशोर लड़कियों की जान चली गई। इज़रायल-अमेरिका धुरी ने कई आम नागरिकों को भी निशाना बनाया। इसी दौरान ईरान का एक नौसैनिक जहाज़, जो भारत के निमंत्रण पर नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत आया था, उसे अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से निशाना बनाया। इस हमले में जहाज़ पर सवार बड़ी संख्या में नाविक मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने भी साहस के साथ पलटवार किया और इज़रायल-अमेरिका धुरी को भारी नुकसान पहुंचाया। इन घटनाओं के बीच भारत की भूमिका उसकी बदलती विदेश नीति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। शुरुआत में भारत गुटनिरपेक्ष था और उसके ईरान के साथ अच्छे संबंध थे। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान भी बहुत अच्छे थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल का दौरा किया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य देश को नहीं बताया गया। इस दौरान उन्हें इज़रायल का सर्वोच्च सम्मान मिला और उन्होंने कहा कि भारत हर परिस्थिति में इज़रायल के साथ खड़ा रहेगा। इसके अगले ही दिन इज़रायल-अमेरिका धुरी ने ईरान पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर कोई ट्वीट नहीं किया और एक सामान्य बयान जारी किया, जिसमें हमलावर और पीड़ित देश को एक ही स्तर पर रख दिया गया। इस तरह प्रधानमंत्री के कुछ कदमों और कुछ मामलों में चुप्पी से यह साफ दिखा कि भारत की नीति तटस्थता से हटकर अमेरिका-इज़रायल धुरी के करीब जा रही है। अब अमेरिका की भूमिका की ओर लौटते हैं। 1950 के दशक से हम अमेरिका की विदेश नीति को देखते आ रहे हैं। उसका रवैया अक्सर दूसरे देशों के मामलों में अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए दखल देने का रहा है। पहले वह दुनिया को साम्यवाद से बचाने को युद्ध छेड़ने का मुख्य आधार बनाता था। इसकी शुरुआत वियतनाम युद्ध से हुई। वियतनाम पहले फ्रांस का उपनिवेश था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सेना ने फ्रांसीसी शासन को हटा दिया। इसके बाद एक जटिल राजनीतिक प्रक्रिया के चलते वियतनाम को 17वें समानांतर के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया गया–कम्युनिस्ट उत्तर वियतनाम और पूंजीवादी दक्षिण वियतनाम। अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ़ भयानक युद्ध शुरू किया और इस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। उसने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया–नेपाम (जेली जैसा पेट्रोल) और एजेंट ऑरेंज (बहुत शक्तिशाली खरपतवार नाशक)। इनका इस्तेमाल जंगल की घनी झाड़ियों और पेड़ों की पत्तियों को साफ़ करने के लिए किया गया, क्योंकि वही जगह वियतकांग के लड़ाकों (वियतनामी लोगों द्वारा संगठित सेना) के लिए स्वाभाविक छिपने की जगह होती थी। नेपाम ने जंगल की झाड़ियों को तो साफ़ किया, लेकिन यह इंसानों से भी चिपक जाता था और भयानक जलन और घाव पैदा करता था। एजेंट ऑरेंज के कारण कई निर्दोष नागरिक मारे गए, खेत-खलिहान नष्ट हो गए और जानवर भी मारे गए। वियतनाम के लोग ज्यादातर हो ची मिन्ह के साथ थे। वियतकांग ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अंततः जीत हासिल की। अमेरिका को पहली बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पांच लाख से अधिक सैनिकों वाली अमेरिकी सेना को एक नए और छोटे देश के हाथों हार के बाद पीछे हटना पड़ा। वियतनाम युद्ध ने यह साफ़ दिखा दिया कि अमेरिका अपने हितों के खिलाफ़ जाने वालों को दबाने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटता, जिसे वह मुक्त दुनिया की विचारधारा के नाम पर पेश करता है। इसके बाद भी अमेरिका ने अलग-अलग बहानों से कई देशों पर हमला किया। इसका दूसरा बड़ा उदाहरण ईरान है। अपनी रणनीतिक स्थिति और विशाल तेल भंडार के कारण ईरान पश्चिमी शक्तियों–खासकर अमेरिका और ब्रिटेन–के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की ईरान में बड़ी मौजूदगी थी। युद्ध के बाद भी उसने एंग्लो-ईरानियन ऑयल कंपनी के जरिए ईरान के तेल पर नियंत्रण बनाए रखा। यह कंपनी ईरान के तेल का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रही थी। लेकिन 1951 में यह स्थिति अचानक बदल गई, जब मोहम्मद मोसद्दिक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का फ़ैसला किया। इसके बाद ब्रिटेन ने मोसद्दिक सरकार का विरोध शुरू किया और उसके खिलाफ़ साज़िशें रचने लगा। उसने अमेरिका को भी अपने साथ लिया और ईरान में तख्तापलट कराया गया। इस तख्तापलट में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर रज़ा शाह पहलवी को सत्ता में बैठा दिया गया, जो अमेरिका का समर्थक था। इस तरह ईरान के तेल पर पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण बना रहा। चिली में साल्वाडोर आयेंदे की सरकार को हटाने की कहानी भी लगभग ऐसी ही है। आयेंदे मार्क्सवादी नेता थे और समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। 3 नवंबर 1970 को उन्होंने चिली के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने अमेरिका के नियंत्रण वाली तांबे की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। 1975 की अमेरिकी सीनेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1970 से 1973 के बीच तख्तापलट की तैयारी में अमेरिका ने गुप्त कार्रवाइयों पर लगभग 80 लाख डॉलर खर्च किए। अमेरिकी अधिकारियों ने आयेंदे सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भी कदम उठाए। अंततः सीआईए के समर्थन से एक तख्तापलट हुआ और सैन्य शासक पिनोशे सत्ता में आ गया। उसका शासन बेहद क्रूर था और उसने चिली के लोकतंत्र और संभावित समृद्धि को गहरा नुकसान पहुंचाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका की नीतियों का असर और भी खतरनाक रहा। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ मदरसों को समर्थन दिया और मुजाहिदीन को प्रशिक्षण दिलाया। इसी प्रक्रिया से बाद में तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठन बने। अमेरिका ने उन्हें लगभग 8000 मिलियन डॉलर की सहायता दी और 7000 टन हथियार भी उपलब्ध कराए (महमूद ममदानी की किताब Good Muslim, Bad Muslim के अनुसार)। 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने का बहाना मिल गया। इस युद्ध में लगभग 60,000 लोग मारे गए। पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने विनाशकारी हथियारों का बहाना बनाकर इराक पर हमला किया। सैनिकों से कहा गया कि सद्दाम हुसैन के शासन में इराक के लोग अत्याचार झेल रहे हैं, इसलिए यह युद्ध जरूरी है। उन्हें यह भी बताया गया कि इराक के लोग उन्हें मुक्तिदाता की तरह देखेंगे और उनका फूलों और चॉकलेट से स्वागत करेंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और निकली। इराक बिखर गया और वहां इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन उभर आए। न तो कोई विनाशकारी हथियार मिले और न ही अमेरिकी सैनिकों का स्वागत हुआ। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद अपने शिकार बने देशों और पूरी दुनिया पर खतरनाक असर छोड़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति ने सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत किया, जिसके दुष्परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। अमेरिकी मीडिया द्वारा इस्लामी आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने और उन्हें लोकप्रिय बनाने से दुनिया भर में मुसलमानों को लेकर नकारात्मक धारणा फैली है। दरअसल, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ही आज दुनिया के कई बड़े संकटों की जड़ में मौजूद हैं। उम्मीद है कि हम साम्राज्यवाद के असर को समझकर शांति को बढ़ावा दे सकेंगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैन्टसर एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/...)

14 और 15 मार्च को होगी पुलिस भर्ती की परीक्षा

मुरादाबाद। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अनुज सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने पुलिस लाइन सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान 14 और 15 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। गोष्ठी में परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

छात्रवृत्ति के आवेदन पेन्डिंग होने पर डीएम सख्त

मुरादाबाद। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षण संस्थान के स्तर पर छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने बैठक में आए शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धकों/प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि ब'चों के छात्रवृत्ति के आवेदन जनपद के विभिन्न कालिजों में पेन्डिंग होने के कारण जनपद की रैंकिंग खराब हो रही है। उन्होंने विभिन्न कालेजों में छात्रवृत्ति के आवेदन पेन्डिंग होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल छात्रवृत्ति के आवेदनों को अग्रसारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के जिन छात्र-छात्राओं का समय रहते आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया गया है उन बच्चों से वार्ता की जाये। छात्रवृत्ति के आवेदनों को अग्रसारित हेतु कालिजों को बार-बार रिमाइन्डर भेजने के बाद भी अग्रसारित न करने/आवेदन अपने स्तर पर ही पेन्डिंग रखने पर जिलाधिकारी ने डिग्री कालिजो की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि कालिजों का छात्रों के प्रति ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कालिजों द्वारा ब'चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाये। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रसारित नहीं किए गये है, उनसे पहले वार्ता करने के साथ ही बयान भी दर्ज किया जाये। जिन कालिजों में बहुत 'यादा संख्या में छात्रवृत्ति के आवेदन छूटे हैं उनकी मान्यता रद्द करने के लिए पत्र भेजा जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कालिजो में पेंडेंसी हैं सभी तत्काल खत्म करें और शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छूटे हैं उनसे वार्ता की जाये और अनुसूचित जाति के छात्रों का आवेदन समय रहते अग्रसारित कर दिया जाये। जिलाधिकारी ने सुखदेई स्मारक महाविद्यालय ठाकुरद्वारा, महावीर कालिज बीजना, आईएफटीएम, केजीके कालिज, टीएमयू, अभय शिक्षा निकेतन कन्या कालेज, हैबिट मुस्लिम कालेज, जेएम पब्लिक कालेज, बंशीसिंह मेमोरियल कालेज, मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कालेज, हरि मंगल विद्यालय आदि को निर्देशित किया कि जो भी छात्रवृत्ति आवेदन की पेंडेंसी है उन आवेदनों को आज ही अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यालयों में पठन-पाठन पर दिया जाये विशेष ध्यानः रामवीर सिंह

मुरादाबाद।

मूंढापांडे ग्राम के रंगोली मंडप में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय के बुनियादी ढांचा को विकसित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों की प्रबंध समिति के सचिवों सहित ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्र'वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुंदरकी विधायक ने कहा कि कायाकल्प योजना के द्वारा प्राथमिक विद्यालय का विकास किया जा रहा है यदि इसमें कहीं भी कमी हो विद्यालय प्रबंध समिति ग्राम प्रधान को या उन्हें बताएं। वह आगे आकर आने वाली समस्याओं का समाधान निकालेंगे।

वह प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यालयों के विकास हेतु सतत प्रयास करने के लिए ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, सचिव एवं प्रधानाध्यापकों के समन्वय से कार्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि शासन की मंशा के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में गरीब असहाय और वंचित वर्ग के ब'चों के पठन-पाठन पर विशेष ध्यान रखते हुए विद्यालय की ओर आकर्षित किया जाए। स्व'छता के पैमाने पर शौचालयों को स्वच्छ किया जाए। उसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। खंड शिक्षा अधिकारी राजेश चतुर्वेदी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित कार्यक्रम व योजना के बारे में जानकारी देते हुए डीवीडी के माध्यम से धनराशि भेजने, निपुण भारत मिशन, विद्यालय प्रबंध समिति एवं आपरेशन कायाकल्प के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य हेतु ग्राम प्रधानों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सचिवों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में नीरज शर्मा, संजय सिंह, आशीष कुमार सिंह, सुमित कुमार, मुनेंद्र यादव ,राजेश सिंह, देवेश चक्रवर्ती, अंजली, सपना सक्सेना, सतेंद्र कुमार, फारुख अली, मुन्ना सिंह, चंद्रशेखर सिंह, मयंक शर्मा आदि उपस्थित रहे।

मस्जिद अबु बकर में मुकम्मल हुआ कुरान

मुरादाबाद। मुकद्दस माहे रमजान शरीफ में नमाजे तरावीह के दौरान कलाम ए पाक मुकम्मल होने का सिलसिला जारी है इसी क्रम में महानगर के करुला आलम शादी हॉल टीले वाली गली में मस्जिद अबू बकर में हाफिज अब्दुल समद ने डेढ़ परे सुनाकर कलाम ए पाक मुकम्मल किया जबकि हाफिज सरफराज सामा रहे। इस दौरान मौलाना सरफराज ने मुल्क की तरक्की खुशहाली और अमन ओ सलामती की दुआ भी विशेष रूप से कराई गई। इस दौरान साहिबेखाना हाजी लाइक साहब व दीगर लोगो की जानिब से हाफिज जी और उनके सामा की गुलपोशी करके इनामात से भी नवाजा गया। इस दौरान नौशाद अली साहब ने तबर्रूक बांटा। इस मौके पर मोहम्मद सरताज, अफजाल अहमद खलील अहमद, अनवर हुसैन, जाकिर अली, हाजी लाइक, फरीद अहमद, हाजी फैसल, तौसीफ अहमद सजाकत हुसैन नौशाद अंसारी काफी तादाद में दुआ में लोगों ने शिरकत की। आखिर में हाजी लईक ने सभी का शुक्रिया के कलमात अदा किये।

राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कराया दूसरा रोज़ा इफ्तार

नई दिल्ली/मुरादाबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन व राज्य सभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा दूसरे रोज़ा इफ़्तार का एहतेमाम उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर किया गया, जिसमे राष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और इफ़्तार से पूर्व देश व दुनिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हुआ और साम्प्रदायिक सौहार्द, आपसी भाई चारा व सामाजिक एकता को मज़बूत करने का सन्देश दिया गया। बाद में देश व दुनिया मे अमन शांति व खुशहाली की दुआ की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ,कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुहम्मद अहमद खान सहित इंडिया एलायंस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

धूम्रपान निषेध दिवस- तंबाकू छोड़ने की दिलाई गई शपथ, निकाली गई जागरूकता रैली

बहराइच।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तंबाकू उत्पादों से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए गोष्ठी, हस्ताक्षर अभियान और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम सीएमओ कार्यालय के सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉ. पारितोष तिवारी ने किया, जिन्होंने उपस्थित लोगों को धूम्रपान न करने और तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने कहा कि तंबाकू उत्पादों के सेवन से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और कैंसर जैसी घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। उन्होंने कोटपा अधिनियम-2003 की जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू की लत छोड़ने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800112356 पर मदद ली जा सकती है। उन्होंने आगाह किया कि स्मोकिंग से लंग कैंसर, सीओपीडी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पैकेट पर चेतावनी लिखे होने के बावजूद लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है।

जिले की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर गोष्ठी व हस्ताक्षर अभियान का हुआ आयोजन

युवाओं और युवतियों में तेजी से बढ़ रही स्मोकिंग की लत

कैंसर डे केयर सेंटर के प्रभारी डॉ. पारितोष तिवारी ने चिंता जताते हुए कहा कि लड़कों के साथ-साथ लड़कियों में भी स्मोकिंग की लत तेजी से बढ़ रही है। पहले यह हाई-प्रोफाइल सोसायटी तक सीमित था, लेकिन अब आम युवतियां भी सिगरेट, वीड, केनेबिस और निकोटीन गम्स का सेवन कर रही हैं। वहीं, एनसीडी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने कहा कि तंबाकू की लत व्यक्ति के साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। युवाओं को जागरूक कर इन बीमारियों से बचाना हम सभी का कर्तव्य है।

शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर है प्रतिबंध

जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी बृजेश सिंह ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा-4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं, धारा-6 के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में और नाबालिगों को तंबाकू बेचना अपराध है। अचल प्रशिक्षण केंद्र में समूह चर्चा (फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन) के बाद आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और सीएचओ ने एक विशाल जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. विजित जायसवाल, डॉ. रियाजुल हक, एफएलसी विवेक श्रीवास्तव, मोहम्मद हारून, शरद श्रीवास्तव, संतोष सिंह, बृज प्रकाश, स्वाती श्रीवास्तव, मुकेश हंस, हरीश कुमार, सीमा कुमारी, अजय प्रताप और मनीष कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।

हरदीप सिंह का वादा- पश्चिम एशिया संकट के बीच भी नहीं रुकेगी सीएनजी - पीएनजी

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि घरों में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और उद्योगों को उनकी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताएं मिलती रहेंगी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में पुरी ने कहा कि आज मीडिया जगत के सदस्यों के साथ अनौपचारिक बातचीत में हमने चर्चा की कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से जारी है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की 100व आपूर्ति सुनिश्चित हो और युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद अन्य उद्योगों को उनकी 70-80व आपूर्ति मिलती रहे। पोस्ट में लिखा था कि हम अपने घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। इससे पहले दिन में, केंद्र सरकार ने घरेलू

ऊर्जा बाजार की सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) लागू किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि अधिनियम लागू करने से प्राकृतिक गैस वितरण के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता सूची तैयार हो गई है, जिससे मौजूदा आपूर्ति संबंधी बाधाओं का प्रबंधन किया जा सके। इस नए आदेश के तहत, घरों के लिए पाइप वाली घरेलू गैस और वाहनों के लिए सीएनजी की 100 प्रतिशत सुनिश्चित आपूर्ति होगी। अन्य क्षेत्रों को पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर निर्धारित आपूर्ति सीमा का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से, चाय उद्योग, विनिर्माण इकाइयों और प्राकृतिक गैस ग्रिड से जुड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत आपूर्ति का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा। इसी प्रकार, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्राकृतिक गैस उपभोक्ताओं के लिए भी आपूर्ति की सीमा पिछले छह महीनों के औसत के 80 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है। सरकार द्वारा संसाधनों के पुनर्संतुलन के तहत उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों के औसत आपूर्ति का 70 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

केरल में दौरे पर पीएम मोदी, कहा- पश्चिम एशिया संकट पर सियासत कर रहा विपक्ष

कोच्चि । मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश के भीतर अफवाह फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया. पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है. हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं. आपको याद रखना है कि आज देश में बीजेपी-एनडीए की सरकार है. जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा है, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है. पीएम मोदी ने कहा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में राजनीति ढूंढ रही है. कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं और हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं, फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने की रील बनाने का अभियान शुरू कर सकें. यही उनका खेल है. मुझे संतोष है कि गल्फ के

हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही हैं. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां देश के भीतर अफवाह फैलाने में जुटी हुई हैं. उन्होंने कहा, आज युद्ध के इस समय में भी कांग्रेस-लेफ्ट और उनका इकोसिस्टम देश में डर पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं. मैं देश से कहूंगा कि कांग्रेस-लेफ्ट की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें, सतर्क रहें. पीएम मोदी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया. उन्होंने कहा, एक तरफ बीजेपी-एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं. कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने मिलकर सरकारें चलाई हैं. इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है. पीएम मोदी ने कहा, वर्तमान संकट ने एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने के महत्व को सिद्ध कर दिया है. ऊर्जा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं. हमने अपनी सोलर एनर्जी क्षमता में बढ़ोतरी की है. केरल में भी सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है. पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

***देश में स्थितियां बिगाड़ना चाहती कांग्रेस- पीएम मोदी**

***अफवाह फैलाने में जुटी कांग्रेस-लेफ्ट- पीएम मोदी**

***कांग्रेस ने देश को विदेशों पर निर्भर रहने वाला बनाया**

ईरान ने शुरू किया इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं

नई दिल्ली । अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। संभावित टारगेट की सूची में गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM और ओरेकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं। इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर भी निशाने पर हो सकते हैं। इस बीच यूएन आज एक प्रस्ताव पर वोटिंग करने वाली है। इसमें ईरान से कहा गया है कि वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर हमले बंद करे।

इजराइली हमलों के बाद लेबनान में 7.8 लाख लोग बेघर

लेबनान में इजराइल के हमले शुरू होने के बाद से करीब 7.80 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। यह जानकारी लेबनान के सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने दी है। सरकार के मुताबिक इनमें से लगभग 1 लाख 20 हजार लोग सरकारी राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसी बीच यूएन ने मंगलवार को सीमा के पास स्थित अल्मा अश-शाब शहर से अपने कर्मचारियों को हटा लिया। यह शहर इजराइल बॉर्डर के पास है और यहां ज्यादातर ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली सेना की कई चेतावनियों के बावजूद यहां के कई लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते थे।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मामूली रूप से घायल

इजराइल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई युद्ध के पहले दिन हुए हमले में मामूली रूप से घायल हो गए थे। यह दावा एक इजराइली अधिकारी ने किया है। इजराइली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन इसी वजह से मुजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हमले के दौरान उनके पैरों में चोट लगी थी, हालांकि चोट कितनी गंभीर है यह साफ नहीं बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों से मोजतबा खामेनेई फिलहाल किसी सुरक्षित और सीक्रेट जगह पर रह रहे हैं।

रिपोर्ट- गूगल-अमेजन ऑफिस पर हमला हो सकता है

राहुल बोले- पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमें बोलने से रोका गया, रविशंकर प्रसाद ने कहा- कभी नहीं

नई दिल्ली । लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए।

इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जब भी बोलने को होते हैं हमे रोका-टोका जाता है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है। कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया। हर समय हमें बोलने से रोका गया। राहुल ने कहा कि आखिरी बार बोलते हुए मैंने प्रधानमंत्री की ओर से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा उठाया था। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल के इतना बोलने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा- नेवर...नेवर। पीएम मोदी का भारत कभी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होगा। इनकी बेसिक समझदारी भी नहीं है। स्पीकर ने कई बार चेयर घेरी गई, कागज फेंके गए, लेकिन वह मुस्कराते रहे। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित करेंगे। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को करीब 7 घंटे बहस हो चुकी है। विपक्षी सांसद ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। 50 से अधिक सांसदों के प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के बाद पीठासीन अधिकारी ने इसे सदन में पेश करने और चर्चा की मंजूरी दी थी।

दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान का ड्रोन अटैक, एक भारतीय समेत चार लोग घायल

नई दिल्ली।

ईरान ने एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया है। इस हमले में एक भारतीय समेत चार लोग घायल हो गए हैं। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक्सपर एक बयान में कहा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अधिकारियों ने दो ड्रोन रोके, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत चार लोग घायल हो गए। इसमें आगे कहा गया, एयर ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा है। ईरान ने अपने इलाके में र और इजरायल के हमलों का जवाब यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कतर और दूसरे खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार करके दिया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है और तेल प्रोडक्शन में रुकावट आई है। गौरतलब है ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जंग दो हफ्तों से जारी है। इस जंग की जद में मध्य पूर्व के देशों को भी भुगतना पड़ रहा है।

ईरान ने पहले भी दुबई एयरपोर्ट के नजदीक हमले किए थे। इसके अलावा शहर के रिहायशी इलाकों में हमले हुए थे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा है कि तेहरान कभी भी क्षेत्रीय देशों के साथ जंग में उलझना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा है कि हमें इलाके के देशों के साथ लड़ाई में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जंग के लिए जिम्मेदार लोगों पर ध्यान नहीं देती है, तो ग्लोबल ऑर्डर और सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी।

कांग्रेस का तंज - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आत्मसमर्पण का प्रमाणपत्र अमेरिका से मिला

नई दिल्ली । कांग्रेस ने भारत को रूस से तेल की खरीदने की अस्थायी रूप से अनुमति दिए जाने संबंधी अमेरिका के ताजा बयान को लेकर बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए आत्मसमर्पण का प्रमाणपत्र है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को समुद्र में पोत पर पहले से मौजूद रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति अस्थायी रूप से दी है और इस अल्पकालिक कदम से रूस को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, अमेरिकी वित्त मंत्री के बाद, अब राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस सचिव की बारी है कि वह प्रधानमंत्री मोदी को आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र दें। उनके अनुसार, मोदी सरकार ने रूस से तेल के आयात को रोकने पर सहमति व्यक्त करके अच्छा व्यवहार किया है और एक इनाम के रूप में अब उसे 30 दिनों की अवधि के लिए ऐसा करने की अनुमति दी गई है। रमेश ने लेविट की टिप्पणियों का एक वीडियो क्लिप साझा किया।

पीएम मोदी ने केरल में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन

कोच्चि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल की अपनी यात्रा के दौरान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का बुधवार को उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस तटीय शहर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रेल मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं की शुरुआत की। मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की एक पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी, दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया (जिनमें से प्रत्येक की लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है) और रेल क्षेत्र में 142 करोड़ रुपये की पहल राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में संपर्क सुविधा बेहतर बनाने और टिकाऊ परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नयी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कार्यक्रम के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित तीन रेलवे स्टेशन- चेरणूर जंक्शन, कुझित्तुरा रेलवे स्टेशन और चंगनाशेरी रेलवे स्टेशन - का भी उद्घाटन किया। करीब 52 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित इन स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है।

आप को नहीं भरोसा- केजरीवाल-सिसोदिया ने आबकारी नीति केस में जज बदलने की मांग की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आबकारी नीति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को बदलने का अनुरोध किया है।

पार्टी ने स्वयं इस घटनाक्रम की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की है। यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों इस मामले में आरोपी हैं। उन्होंने अपने पत्र में मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की बात कही है।

पत्र में वर्तमान न्यायाधीश द्वारा सुनवाई जारी रखने पर कुछ आपत्तियां उठाई गई है। हालांकि, उन आपत्तियों का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास ऐसे अनुरोधों पर विचार करने का अधिकार होता है। यह कदम मामले को न्यायिक प्रक्रिया में एक नया मोड़ लेकर आया है। पार्टी का कहना है कि यह न्याय की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इस नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की थी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यह मामला दिल्ली की राजनीति में काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है।

एलपीजी का संकट मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा- प्रियंका गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि देश में रसोई गैस एलपीजी की कथित किल्लत मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जनता कितना बर्दाश्त करेगी? लोकसभा सदस्य ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा, लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और अब एलपीजी के लिए जूझ रहे हैं। यह मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सदन में इन मुद्दों पर चर्चा होती तो अच्छा होता और सदस्य वहां जनता के सवाल उठा पाते।

देशभर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें

नई दिल्ली ।

अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देशभर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बन पा रहा है।

■ यूपी-बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बंट रहे है, राजस्थान में कालाबाजारी

मध्य प्रदेश- कैटरर्स बोले- ये इमरजेंसी जैसी स्थिति

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से सबसे ज्यादा संकट होटल-रेस्टोरेंट पर है। वहीं घरेलू रसोई गैस लेने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। जिन घरों में शादी है, वे टेंशन में है। अकेले भोपाल में ही 20 दिन में एक हजार से ज्यादा शादियां है। कैटरर्स का कहना है कि ये इमरजेंसी जैसी स्थिति है।

उत्तर प्रदेश- पुलिस सुरक्षा में बंट रहे सिलेंडर

उत्तर प्रदेश में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे है। गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगने लगी है। गोरखपुर-सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। एजेंसियों पर तड़के 3 बजे से ही लोग लाइन लगाने पहुंच रहे है। घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। वजह- सिलेंडर कम हैं और लेने वालों की संख्या ज्यादा।

बिहार- लोग सुबह से ही गैस एजेंसी पहुंच रहे

यहां भी 2 दिन से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद है। इस वजह से होटल,रेस्टोरेंट पर असर पड़ा है। घरेलू गैस को लेकर भी राज्य के कई जिलों में लोगों की लंबी कतार दिखी। गोपालगंज, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना समेत कई जिलों में लोग सुबह से ही गैस एजेंसी पहुंचने लगे। कई एजेंसियों में ताला लटका है। कोई कर्मचारी भी वहां मौजूद नहीं हैं।

राजस्थान- 1900 रुपए का सिलेंडर 2500 रुपए में

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे में अलग-अलग एजेंसी तय दाम से ज्यादा में सिलेंडर की कालाबाजारी कर रही है। स्टिंग में खुलासा हुआ कि जयपुर में 1911 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 2500 रुपए तक में बेचा जा रहा है।

पंजाब-घरेलू सिलेंडरों की भी बुकिंग बंद

लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने के कारण घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला समेत कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद है।

गुजरात- कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 2500 से 3000 रुपए तक की मांग

मशहूर फूड ट्रक महेश पौनभाजी के मैनेजर शिवचरण अग्रवाल के अनुसार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए फिलहाल 2500 से 3000 रुपए तक की मांग की जा रही है। इस कालाबाजारी के कारण छोटे-मोटे दुकानदार और होटल मालिकों पर आर्थिक संकट आ गया है। घरेलू गैस के लिए भी राज्य के कई जिलों में लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है।

संकट से निपटने सरकार ने 5 जरूरी कदम उठाए

1. हाई-लेवल कमेटी बनाई - संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तीन तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है, जो सप्लाई की समीक्षा करेगी।

2. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू- गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है।

3. 25 दिन बाद होगी एलपीजी बुकिंग- घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक होगा।

4. ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य -गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं।

5. एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश

सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया था। सूत्रों का कहना है कि अब उत्पादन 10फीसदी बढ़ गया है।